# महादलितों की योजनाओं की होगी मानीटरिंग

- इस वर्ष 15.20 लाख महादलितों को रेडियो
- महादलित परिवारों को इंदिरा आवास दिए जाने को ले विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी एक्शन प्लान बनायेगी

अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी एवं आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

जागरण ब्यूरो, पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को महादलित विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा को ले बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। यह निर्णय लिया गया कि विकास मित्र महादलित परिवारों के लिए चलने वाली विकास योजनाओं की मानीटरिंग करेंगे। उनका दायित्व चेंज एजेंट के रूप में रहेगा। जिलाधिकारियों व अन्य अधिकारियों को यह हिदायत दी गयी है कि विकास मित्र से महादलित परिवार की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य काम नहीं लिए जाएं।

आज की बैठक में यह तय हुआ कि हर महादलित टोलों में फलदार वृक्ष लगाये जाएंगे। इन फलदार वृक्षों की संख्या दो सौ हो जाने पर एक मानक दिवस मनाया जाएगा। इसमें चार महादलित परिवार जुड़ेंगे। महादलित परिवार तीन सालों तक इसकी देखभाल करेंगे। तीन साल के बाद एक-एक महादलित परिवार को बीस फलदार वृक्ष का पट्टा दे दिया जायेगा। अगर पेड़ शीशम या सखुआ का है तो बीस साल बाद पेड़ के सूख जाने पर उसकी लकड़ी पर उस महादलित परिवार का हक होगा।

मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद भू राजस्व विभाग के प्रधान सचिव डा. सी अशोक वर्द्धन को यह निर्देश दिया कि सभी महादलित परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाये। जिन महादलित परिवारों को जमीन आवंटित हो चुका है पर मकान नहीं बना है के लिए विकास आयुक्त फूल सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी शीघ्र एक्शन प्लान तैयार करेगी। बैठक में उपस्थित अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग के सचिव व बिहार महादलित विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएम राजू ने बताया मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत 40 हजार से अधिक लाभान्वितों को जोड़ा जाए। महादलित टोलों में तीन हजार से अधिक सामुदायिक भवनों का निर्माण होगा। निर्माण कार्य पूरा किए जाने का दायित्व विकास मित्र, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी व जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया है। 62.12 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15.20 लाख महादलितों को रेडियो दिया जाएगा। सभी एससी-एसटी विद्यालयों में जूडो-कराटे का प्रशिक्षण आरंभ किया जाएगा।